अमेरिका के साथ मिलकर टैंक व दूसरे युद्धक विमान बनाएगा भारत

अमेरिका की ओर से दिए गए प्रस्ताव को भारत ने किया स्वीकार

- टू प्लस टू वार्ता में रक्षा सहयोग के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा
- 38 देशों के संयुक्त समुद्री बल में भी शामिल होगा भारत

नई दिल्ली में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उनके अमेरिकी समकक्ष लायड आस्टिन (एकदम बाएं) और जयशंकर • रायटर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत और अमेरिका मिलकर टैंक और दूसरे युद्धक वाहनों का निर्माण करेंगे। इस बारे में प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से ही आया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया है। 10 नवंबर, 2023 को दोनों देशों के बीच हुई टू प्लस टू वार्ता में इसको लेकर बात हुई और फैसला किया गया कि आपसी सहयोग से सेना में इस्तेमाल होने वाले युद्धक वाहनों (टैंक आदि) को विकसित किया जाएगा और सह निर्माण किया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने का भी फैसला किया है।

भारत और अमेरिका के रक्षा व विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में रक्षा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वार्ता के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इस बात की जानकारी दी और बाद में अमेरिका के रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने भी पत्रकारों से अलग से हुई एक बातचीत में इसकी पुष्टि की। टू प्लस टू वार्ता में आस्टिन के अलावा अमेरिकी टीम में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी के अलावा कुछ दूसरे अधिकारी थे। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश सचिव विनय क्वात्रा, रक्षा सचिव अरमाने, अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधु व कुछ दूसरे अधिकारी कर रहे थे। आस्टिन ने कहा कि हम साथ मिलकर एक युद्धक वाहन बनाना चाहते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना होगी। भारत को एमक्यू-9बी ड्रोन देने के सवाल पर आस्टिन ने कहा कि इस बारे में सही समय पर घोषणा होगी। जहां तक अमेरिका की बात है तो वह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने में जो भी मदद की दरकार है, उसे उपलब्ध करा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसमें देरी ना हो।

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी समकक्ष आस्टिन से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। खास बात यह रही कि भारत ने संयुक्त समुद्री बल में शामिल होने की रजामंदी जता दी है। इसका मुख्यालय बहरीन में है। अमेरिका और इसके कुछ प्रमुख नाटो देशों की अगुआई में गठित 38 देशों का यह संगठन अरब सागर, हिंद महासागर, ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी के क्षेत्र में कानून सम्मत व्यवस्था कायम रखने का काम करता है। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इटली, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, थाइलैंड, तुर्किये और पाकिस्तान जैसे देश इसके सदस्य हैं। भारत अब इसका पूर्णकालिक सदस्य होगा। यह सदस्य देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के अलावा आपसी सहयोग का भी मंच प्रदान करता है। उधर, राजनाथ सिंह ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के कुछ सामान अमेरिकी रक्षा मंत्री को भेंट की। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कई अमेरिकी सैनिक जापान के साथ युद्ध करते हुए असम के आसपास मारे गए थे। इनकी वर्दियां व दूसरे सामान बाद में मिले, जिसे अभी तक सुरक्षित करके रखा गया है।

टू प्लस टू वार्ता में चीन के अतिक्रमण और आतंकवाद पर भी चर्चा

नई दिल्ली : हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए भारत व अमेरिका ने अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने का निर्णय किया है। दोनों देशों में कूटनीतिक व रणनीतिक संबंधों पर निर्णय लेने के लिए बनी टू प्लस टू वार्ता व्यवस्था के तहत पांचवीं बैठक में चीन के अतिक्रमण व पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का भी मुद्दा उठा। देखें » 32